40वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च 2012
दिसम्बर 2011 त्रैमास तक की प्रगति की समीक्षा

कार्य बिन्दू

क्र.सं0.	कार्य बिन्दू	कार्रवाई	प्रगति
1	प्रमुख सचिव (उद्योग) ने कहा कि पहाडी जिलों का ऋण जमा अनुपात बहुत कम है और प्रत्येक एस.एल.बी.सी. की बैठको में इसे बढाने हेतु चर्चा की जाती रही है परन्तु इस दिशा में समभावित प्रगति नहीं हो रही हैं। उन्होंने बैंको को निर्देशित किया कि जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स कमेटी गठित की जाय जो ऋण जमा अनुपात बढाने हेतु सुझाव दे, जिसमें स्टोन क्रशिंग यूनिट एवं लघु जलविद्युत योजनाएं भी सम्मिलित की जा सकती हैं।	सभी बैंक /अग्रणी जिला प्रबन्धक/उद्योग विभाग / एस0एल0बी0सी0 जिला स्तर पर गठित सी0डी0 रेश्यो समिति ही टास्क फोर्स समिति का कार्य करेगी और चिन्हित विकास योजनाओं / क्रियाकलापों की प्रगति, जिसमें स्टोन क्रशिंग यूनिट एवं लघु जलविद्युत योजनाएं भी सम्मिलित की जा सकती हैं, पर समीक्षा करे और रिपोर्ट एस0एल0बी0सी0 को अविलम्ब प्रेषित करेगी। राज्य स्तर पर होने वाली अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थाई समिति की बैठक में इसकी समीक्षा की जायेगी।	
2.	बैंक जिनका ऋण जमा अनुपात 30 प्रतिशत से कम है, उन्हे अपने ऋण जमा अनुपात बढाने हेतु ठोस कदम उठाने होंगे।	सेन्ट्रल बैंक / पजाब एंड सिध बैंक/ यूको बैंक/यूनाईटेड बैंक/इन्डियन बैंक	
3.	वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत सम्बन्धित बैंको को आवंटित गाँवों में लिंक शाखा के किसी अधिकारी द्वारा सप्ताह के प्रत्येक बुद्धवार को गाँवों में बिजनेस कॉरेस्पान्डेन्ट (बी.सी.) द्वारा किये गये कार्य की निगरानी एवं ग्रामीणों के बैंकिंग से सम्बन्धित समस्याएं का निराकरण करने हेतु दौरा करें। इस आशय का एक नोटिस बोर्ड बी.सी. के कार्यस्थल पर लगाना सुनिश्चित करें, जिसपर दौरा करने वाले अधिकारी / बी.सी. का नाम, मोबाईल नम्बर तथा दिन व समय अंकित हो।	वित्तिय समावेशन लिंक बेस शाखा	
4.	2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में, बिजनेस कॉरेस्पान्डेन्ट (बी.सी.) द्वारा कम से कम 300 जमा खाते एवं प्रत्येक कृषक को के0सी0सी0 / जी0सी0सी जारी किये जायें।	सभी बैंक //अग्रणी जिला प्रबन्धक	

5.	सचिव (वित्त) ने बी0एस0एन0एल0 को कहा कि राज्य के सभी अटल आदर्श ग्रामों एवं 1000 से 1999 तक के जनसंख्या वाले गाँवों में संचार सुविधा (Broad Band / GPRS Connectivity for Data transmission) शीघ्र उपलब्ध करायें।	सम्बन्धित बैंक / बी.एस.एन.एल.	
6.	वार्षिक ऋण योजना 2011-12 के लक्ष्यों के सापेक्ष जिन बैंको की उपलब्धि 50 प्रतिशत से कम है, उन्हें इस ओर सार्थक प्रयत्न कर मार्च 2012 तक शत प्रतिशत उपलब्धि दर्ज करनी होगी।	यूनाईटेड बैंक / बैंक ऑफ इन्डिया / इलाहाबाद बैंक / विजया बैंक / एस.बी.पी./ पजाब एंड सिध बैंक	
7.	प्रमुख सचिव (उद्योग) ने सभी अग्रणी जिला प्रबन्धक को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 की वार्षिक ऋण योजना संकलित करते समय प्रत्येक जिले में 4-5 क्रशर / खनन ईकाईयों को भी सम्मिलित किया जाय।	अग्रणी जिला प्रबन्धक / सभी बैंक	
8.	बैठक में निर्णय लिया गया कि एस.एल.बी.सी. की तर्ज पर सभी अग्रणी जिला प्रबन्धक अपने जिला की जिला परामर्शदात्री समिति / जिला स्तरीय समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठकों की तिथियों का कैलेन्डर तैयार कर, जिला अधिकारी द्वारा अनुमोदित करा लें।	अग्रणी जिला प्रबन्धक / जिलाधिकारी	
9.	अध्यक्ष महोदय ने कृषि विभाग को पुनः निर्देशित किया कि वह जिला के सभी पात्र कृषकों की सूची सम्बन्धित अग्रणी प्रबन्धक को प्रेषित करे ताकि बैंको द्वारा उन्हें के0सी0सी0 जारी करवाये जा सके।	निदेशक (कृषि) / मुख्य राजस्व अधिकारी	
10.	निदेशक कृषि ने कहा कि बैंको में बरती जा रही फसल बीमा से सम्बन्धित अनियमितताओं को दूर किया जाय तथा जिला अधिकारी की अधयक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया जाय, जिसमें अग्रणी जिला प्रबन्धक, नाबार्ड, कृषि विभाग व कृषि बीमा कम्पनी की सहभागिता सुनिश्चित की जाय।	जिलाधिकारी / अग्रणी जिला प्रबन्धक / कृषि विभाग / नाबार्ड / कृषि बीमा कम्पनी	
11.	आर-सेटी में दिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्ष 2012-13 का कैलेन्डर तथा व्यय किये जाने वाली राशियों को ब्यौरा बनाकर जिले की स्थानीय परामर्शदात्री समिति में प्रस्तुत कर वार्षिक बजट अनुमोदित करवा लें ।	अग्रणी जिला प्रबन्धक / निदेशक आरसेटी / डी.आर.डी.ए. / नाबार्ड	
12.	प्रमुख सचिव (उद्योग) ने ग्राम्य विकास एवं उद्योग विभाग को निर्देशित किया कि वह आर-सेटी स्थापित करने हेतु उत्तकाशी, नैनीताल एवं चम्पावत में शीघ्र भूमि उपलब्ध करायें।	ग्रामीण विकास विभाग / उद्योग विभाग / निदेशक आरसेटी	

13.	सचिव (वित्त) ने सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया कि वह केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा पोषित विकास योजनाओं से सम्बन्धित ् अनुदान राशियों को सम्बन्धित बैंको में ऑन-लाईन ट्रान्सफर करें।	सम्बन्धित सरकारी विभाग / बैंक	
14.	प्रमुख सचिव (उद्योग) ने के.वी.आई.सी. एवं के.वी.आई.बी. को निर्देशित किया कि वे बैंकों के लम्बित अनुदान राशि शीघ्र अति शीघ्र प्रेषित करें।	के.वी.आई.सी. / के.वी.आई.बी.	
15.	सचिव (वित्त) बैंको को निर्देशित किया कि उनके द्वारा जारी किये ऋण वसूली प्रमाण पत्रों का मिलान जिला राजस्व कार्यालय (C.R.A.) से कर लें और वसूली में तेजी लाने हेतु जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करें।	सभी बैंक / जिलाधिकारी	
16.	सभी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक मार्च 2012 तक के एस0एल0बी0सी0 डाटा (विवरणी 1-48) जाँच कर दिनांक 15 अप्रैल 2012 तक अनिवार्य रूप से ई-मेल द्वारा एस0एल0बी0सी0 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें । इसी क्रम में अवगत कराना है कि गर्वनर, भारतीय रिजर्व बैंक, की अध्यक्षता में एस0एल0बी0सी0 की एक विशेष बैठक माह मई 2012 में आयोजित की जानी प्रस्तावित है।	सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक	

****

40TH STATE LEVEL BANKERS' COMMITTEE,
MEETING HELD ON 20thMARCH 2012 AT HOTEL PACIFIC, DEHRADUN
REVIEW OF PERFORMANCE FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 2012

ACTION POINTS

Sr.No.	Action Points	Action to be initiated by	Progress
1.	Principal Secretary (Industries) stated that improving CD Ratio in Hill District is a perennial problem and the issue is being discussed in each SLBC meeting without improvement. He advised in the new Industrial Policy - Stone Crusher / Mining have been legally opened up. He directed that a task force for improvement in CD Ratio be constituted and a few activities suitable for Hill regions such as Stone Crushing, Mining,Tourism, Micro Hydel Projects be identified and the presentation on progress be made.	Banks / LDMs / Industries Deptt. District CD Ratio Committee would also function as task force for the district to monitor the progress under identified activities like stone crushing, mining, Micro Hydel Projects. While at State Level, Standing Committee for Infrastructure Development would monitor the progress. Distt. CD Ratio Committee will immediately submit the report 10 days before the scheduled SLBC meeting.	
2.	Banks whose CD Ratio is below 30% should initiate steps to improve the same.	Central Bank / P&SB / UCO Bank / United Bank / Indian Bank	
3.	Villages allotted under FIP should be visited by the Officer from the link branch on weekly basis preferably Wednesday, a notice board to that effect, date of visit, time of visit and contact No. of the concerned official should be displayed at Panchayat Bhawan or other prominent place. The Branch should introduce the BC as authorised agent to transact banking business.	FIP village Base-Branch	

4.	The villages with population above 2000 which are covered with Business Correspondents, minimum 300 deposit accounts should be opened and each farmer be covered with KCC / GCC Card.	All Banks / LDMs	
5.	Secretary (Finance) requested BSNL to provide connectivity in Atal Adarsh Villages with population above 1000 to 1999.	Concerned Banks / BSNL	
6	Banks whose achievement under ACP is less than 50% should ensure that targets are achieved by 31st March.	United Bank / Bank of India / Alld Bank / Vijaya Bank / SBP / P&SB	
7.	Annual Credit Plan for 2012-13 should incorporate provision of 4/5 Crushers, Mining per District as desired by Principal Secretary (Industries) in the meeting.	LDMs / Banks	
8.	The Calendar for holding District Consultative Committee(DCC) meeting be finalised and communicated to the member banks / agencies.	LDMs / DMs	
9.	Agriculture Department to provide list of eligible farmers in the State to the respective LDMs so that KCC can be issued to them.	Director (Agri) / Chief Revenue Officer	
10.	There were several deficiencies committed in the Crop Insurance which were highlighted in the sample survey conducted by the Director (Agri). It was directed that as mentioned in the Principal Secretary (Agri) letter No. 82/III(i) dated 27.01.2012, District Level Monitoring Committee presided over by the DM with members - LDM, Agriculture Deptt, NABARD, Crop Insurance Deptt. be activated so that the deficiencies in the implementation of scheme are timely rectified and recurrence avoided.	DM, / LDM / Agriculture Deptt, / NABARD / Crop Insurance Deptt.	

11	Programmes to be conducted at R-Seti for the Calendar year 2012-13 and the expenditure to be incurred, be got approved in Local Advisory Committee Meeting and be advised to Govt. / NABARD / Bank for making budgetary provision and advance sanction of training cost.	LDMs / R-Seti / DRDA/ NABARD	
12.	Principal Secretary (Industries) directed the Rural Development Deptt. / Industries Deptt. to provide land at Uttarkashi, Nainital and Champawat for establishing R-Seti without further loss of time.	Rural Development Deptt./ Industries Deptt. / Drector R-Seti	
13.	Secretary (Finance) directed the concerned deptt. for on-line transfer of funds / subsidies relating to Centrally and State sponsored development schemes.	Concerned Govt. Deptt. / Banks	
14.	Principal Secretary (Industries) directed the KVIC / KVIB to settle pending subsidies cases on urgent basis.	KVIC / KVIB / Concerned Banks	
15.	Secretary (Finance) directed the banks to reconcile the RCs with the District authorities and where the RC are outstanding for more than one year, the bank should take up the matter with District Authorities for speeding up the recovery.	All Banks / District Authorities	
16	All Banks / LDMs to submit complete, duly verified SLBC data for the year ended 31st March 2012 (SLBC return 1 to 48) to the SLBC by e-mail latest by **15th April 2012**. In this connection , a special SLBC meeting with Governor, RBI is also proposed during May 2012.	All Banks / LDMs	

****